करेंट अफेयर्स 23 जून, 2022

https://t.me/raceiaslucknow

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)

सिलेबस: जीएस पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी , विकास,विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले आठ वर्षोंमें 10 अरब डॉलर से आठ गुना बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है और देश बायोटेक में शीर्ष 10 देशों की लीग तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। - वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र।

BIO ECONOMY क्या है?

- जैव-अर्थव्यवस्था या जैव-आधारित अर्थव्यवस्था उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए एक नया मॉडल है ।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, जैव-अर्थव्यवस्था "जैविक संसाधनों काउत्पादन, उपयोग और संरक्षण है, जिसमें संबंधित ज्ञान, विज्ञान,प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं, ताकि एक स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्रों को जानकारी, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को प्रदान किया जा सके"।

जैव-अर्थव्यवस्था की आवश्यकता

- जीवाश्म ईंधन से जैव-आधारित अर्थव्यवस्था में संक्रमण से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और अधिक स्थिरता प्राप्त करने की उम्मीद है, जिससे जलवायु औरपर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा।
- यह लाखों टन जैविक अपशिष्ट औरअवशिष्ट सामग्री के भीतर संग्रहीत अप्रयुक्त क्षमता का भी शोषण करता है।
- जैव-अर्थव्यवस्था, हाल के वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर परराजनीतिक और तकनीकी हित का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।

BIRAC के बारे में

ज् जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) एक गैर-लाभकारी, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारत सरकार द्वारा एक इंटरफेसएजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, जो उभरते बायोटेक उद्यम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को पूरा करते हुए रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाता है।

- BIRAC का उद्देश्य 100 बिलियन अमरीकी डालर की भारतीय जैव-अर्थव्यवस्थाके निर्माण में एक परिवर्तनकारी और उत्प्रेरक भूमिका निभाना है ।

RACE IAS

- यह एक उद्योग-अकादमिक इंटरफ़ेस है जो प्रभावपहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से अपने जनादेश को लागू करता है जैसे:
    1. लक्षित वित्त पोषण के माध्यम से जोखिम पूंजी तक पहुंच प्रदान करना
    2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
    3. आईपी प्रबंधन
    4. हाथ से चलने वाली योजनाएं जो बायोटेक फर्मों के लिए नवाचार उत्कृष्टता लाने में मदद करती हैं और उन्हेंविश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती हैं।
- अपने अस्तित्व के आठ वर्षों में, BIRAC ने कई योजनाओं, नेटवर्कों और प्लेटफार्मों की शुरुआत की है जो उद्योग-अकादमिक नवाचार अनुसंधान में मौजूदा अंतराल को पाटने में मदद करते हैं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपन्यास,उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उत्पादों के विकास को सुविधाजनक बनाते हैं।
- बीआईआरएसी ने अपने जनादेश की मुख्य विशेषताओं को सहयोग करने और वितरित करने के लिए कई राष्ट्रीय औरवैश्विक भागीदारों के साथ साझेदारी शुरू की है।

भारतीय जल क्षेत्र से चार नए कोरल दर्ज किए गए

सिलेबस: प्रीलिम्स

वैज्ञानिकों ने भारतीय जल क्षेत्र से पहली बार कोरल की चार प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है।

तथ्यों

- अंडमान **औरनिकोबार द्वीप समूह** के पानी से **एज़ुऑक्सैन्थेलेट कोरल** की ये नई प्रजातियां पाई गई थीं।
- Azooxanthellate कोरल कोरल का एक समूह है जिसमें एज़ुऑक्सैन्थेला नहीं होता है और सूर्य से नहीं बल्कि प्लवक के विभिन्न रूपों पर कब्जा करने से पोषण प्राप्त होता है।
- कोरल के ये समूह गहरे समुद्र के प्रतिनिधि हैं , जिनमें से अधिकांश प्रजातियां 200 मीटर से1000 मीटर के बीच रिपोर्ट करती हैं। उथले तटीय जल से भी उनकी घटनाओं की सूचना दी जाती है।
- ये चार प्रजातियां इस प्रकार हैं:
    1. Truncatoflabellum crassum
    2. T.incrustatum
    3. टी. aculeatum
    4. टी अनियमित
- ये azooxanthellate कोरल जो Flabellidae परिवार के तहत आते हैं, पहले जापान से फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई पानी मेंपाए गए थे, जबकि अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित इंडो-वेस्ट पैसिफिक वितरण की सीमा के भीतर केवल टी क्रैसम की सूचना दी गई थी।

RACE IAS

G–7 शिखर सम्मेलन

सिलेबस: जीएस पेपर-II (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान)

संदर्भ: पीएम मोदी 26 और 27 जून को आयोजित होने वाले जी -7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे ।

- 48 वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक Schloss Elmau, Krün,Bavarian Alps, जर्मनी में आयोजित किया जाना है।

G–7 के बारे में

G7 या Group of Seven अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं काएक समूह है। सात देश कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।

- वैश्विक आर्थिकशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की सालाना बैठकें होती हैं।
- सभी जी-7 देश और भारत जी-20 का हिस्सा हैं।
- जी -7 में एक औपचारिक संविधान या एक निश्चित मुख्यालय नहीं है । वार्षिक शिखर सम्मेलनों के दौरान नेताओं द्वारालिए गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।

CRYPTOCURRENCY

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर-III (संसाधनों, आईटी और कंप्यूटरों का जुटाव)

संदर्भ: क्रिप्टो बाजार की मंदी ने क्रिप्टोकरेंसी को लाइमलाइट मेंला दिया है।

CRYPTOCURRENCY के बारे में

- एक cryptocurrency एक नेटवर्क पर आधारित डिजिटल या आभासी मुद्रा का एक रूप है जो बड़ी संख्या में कंप्यूटरों में वितरित कियाजाता है। नकली या डबल-खर्च करना लगभग असंभव है ।
- कई cryptocurrencies **blockchain प्रौद्योगिकी** पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क हैं.
- Cryptocurrencies आमतौर पर किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। इसलिए, यह उन्हेंसैद्धांतिक रूप से सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर के लिए प्रतिरक्षा बनाता है।
- कंप्यूटर विशेषज्ञों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी की श्रेणी में आने वाली किसी भी प्रणाली को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूराकरना चाहिए:

1. किसी भी केंद्रीकृत प्राधिकरण की अनुपस्थिति और वितरित नेटवर्क के माध्यम से बनाए रखा जाता है।
2. सिस्टम cryptocurrency इकाइयों के रिकॉर्ड बनाए रखता है और जो उन्हें मालिक है.

RACE IAS

3. प्रणाली तय करता है कि क्या नई इकाइयों को बनाया जा सकता है और यदि यह करता है, तो मूल और स्वामित्व की शर्तों का फैसला किया।
4. cryptocurrency इकाइयों के स्वामित्व को विशेष रूप से cryptographically साबित किया जा सकता है।
5. सिस्टम लेनदेन करने की अनुमति देता है जिसमें क्रिप्टोग्राफिक इकाइयों का स्वामित्व बदल जाता है।

CRYPTOCURRENCIES के प्रकार

- क्रिप्टो मुद्रा का पहला प्रकार **बिटकॉइन** था , जो आज तक सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला, मूल्यवान और लोकप्रिय बना हुआ है। बिटकॉइन के साथ- साथ, कार्यों और विनिर्देशों की अलग-अलग डिग्री के साथ अन्य वैकल्पिक क्रिप्टोकरेंसी बनाई गई हैं।

Bitcoin को 2009 में एक व्यक्ति या समूह द्वारा लॉन्च किया गया था जिसे छद्म नाम "सतोशीनाकामोतो" द्वारा जाना जाता है।

- बिटकॉइन की सफलता के परिणामस्वरूप बनाई गई प्रतिस्पर्धी क्रिप्टोकरेंसी को altcoins के रूप मेंजाना जाता है। प्रसिद्ध altcoins में से कुछ इस प्रकार हैं:

1. Litecoin
2. Peercoin
3. Namecoin
4. Ethereum
5. कार्डाना

CRYPTOCURRENCY के फायदे

Cryptocurrency के निम्नलिखित फायदे हैं:

1. दो पक्षों के बीच धन हस्तांतरण क्रेडिट / डेबिटकार्ड या बैंकों की तरह तीसरे पक्ष की आवश्यकता के बिना आसान हो जाएगा।
2. यह अन्य ऑनलाइन लेनदेन की तुलना में एक सस्ता विकल्प है।
3. भुगतान सुरक्षित और सुरक्षित हैं और गुमनामी का एक अभूतपूर्व स्तर प्रदान करते हैं।
4. आधुनिक cryptocurrency सिस्टम एक उपयोगकर्ता "बटुआ" या खाता पता है जो केवल एक सार्वजनिक कुंजी और समुद्री डाकू कुंजी द्वारा सुलभहै के साथ आते हैं. निजी कुंजी केवल बटुए के मालिक को पता है।
5. धन हस्तांतरण न्यूनतम प्रसंस्करण शुल्क के साथ पूरा कर रहे हैं.

CRYPTOCURRENCY के नुकसान

1. cryptocurrency लेनदेन की लगभग छिपी हुई प्रकृति उन्हें इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग, कर-अपवंचन और संभवतः यहां तक कि आतंक-वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों काध्यान केंद्रित करना आसान बनाती है।
2. भुगतान अपरिवर्तनीय नहीं हैं.
3. Cryptocurrencies हर जगह स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कहीं और सीमित मूल्य है

RACE IAS

4. चिंता है कि Bitcoin जैसी cryptocurrencies किसी भी भौतिक माल में निहित नहीं हैं। हालांकि, कुछशोधों ने पहचान की है कि बिटकॉइन के उत्पादन की लागत, जिसके लिए तेजी से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सीधे इसके बाजार मूल्य से संबंधित है।

भारत और CRYPTOCURRENCY

- 2009: पहली cryptocurrency, Bitcoin 2009 में Satoshi Nakamoto द्वारा लॉन्च किया गया था।
- 2018: RBI ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो लेनदेन का समर्थन करने से प्रतिबंधित कर दिया।
- 2019: अंतर-मंत्रालयी समिति ने सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की ।
- 2020: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के व्यापार पर प्रतिबंध को असंवैधानिक के रूप में खारिज कर दिया।
- 2021: क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का विनियमन पेश किया गया।

  - इसके तहत , निजी डिजिटल मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने की योजना आरबीआई समर्थित मुद्रा के पक्ष में है ।

  - व्यापार, खनन और क्रिप्टो जारी करने पर प्रतिबंध लगाने से पहले एक 3-6 महीने की निकास अवधि ।

  अंत में, Cryptocurrencies, हालांकि अनियमित, भारत में अवैध नहीं हैं ।

RACE IAS